

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 232*
09 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

*232. श्री संतोष कुमार:

श्री रेबती त्रीपुरा:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का निकट भविष्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने हेतु अनुदान प्रदान करने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो विशेषकर बिहार में पूर्णिया जिले सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं उत्तर प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का विशेषकर बिहार में पूर्णिया जिले सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों को लाभान्वित करने हेतु लघु खाद्य पार्कों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;
- (घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजनागत रूपरेखा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या छोटे और मध्यम किसानों को लाभान्वित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित कोई अन्य योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्रीमती हरसिमरत कौर बादल)

(क)से(ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में 09 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 232* के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): प्रस्तावित ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता दिए जाने और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने उत्पादन क्षेत्रों के निकट आधुनिक अवसंरचना का सृजन करने के लिए "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जुलाई, 2017 में "कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन" स्कीम शुरू की थी। बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में अनुमोदित की गई परियोजनाओं (30 जून, 2019 तक) का ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

(ड): प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत सभी प्रमुख स्कीमों अर्थात् मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन, बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन तथा ऑपरेशन ग्रीन्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को लाभ पहुंचाती हैं।

सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में 09 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 232* के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमकेएसवाई की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित की गई परियोजना निष्पादन एजेंसी

(30.06.2019 तक की स्थिति)

राज्य	आवंटित किए गए स्लॉटों की संख्या	प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या
बिहार	5	3	1
उत्तर प्रदेश	12	16	2
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0
असम	2	1	0
सिक्किम	1	0	0
त्रिपुरा	1	0	0
मणिपुर	1	2	1
मेघालय	1	0	0
मिजोरम	1	1	0
नागालैंड	1	1	0
कुल	26	24	4

